HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 364/2025

Devendra Gurjar S/o Shri Pannalal,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Revision Petition No. 792/2022

Ram Swaroop Son Of Kanaram

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 5577/2023

Varun Jain S/o Shri Vijay Jain,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

S.B. Criminal Writ Petition No. 703/2024

Govind Parashar S/o Mohan Lal Sharma

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 7547/2024

Munnu Lal Maurya S/o Late Shri Paltu Prasad Maurya,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 8221/2024

Manoj Kumar Khinchi S/o (Late) Shri Gyarsilal,

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan

----Respondent

RAJASTHAN HIGH COURT

For Petitioner(s)	:	Mr. Manish Gupta Mr. V. R. Bajwa Mr. Virendra Agrawal Mr. Rishi Kumar Sharma Mr. Jay Bhardwaj Mr. Anil Kumar Sharma Mr. Manjeet Sharma Ms. Shreya Hatila
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Pradeep Choudhary, Spl. Counsel C.B.I. Mr. Pradeep Choudhary Mr. C. S. Sinha

---

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

22/05/2025

याची देवेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में उनके मामले में न्यायालय द्वारा कार्यवाही को स्थगित नहीं किया गया है, अतः जब तक अन्य प्रकरणों में जो इस प्रकरण के साथ सूचीबद्ध हैं और टैग हैं उनमें अन्य याचीगण के संदर्भ में आपराधिक कार्यवाही को स्टे किया गया है। अत : ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में भी जब तक याचिका का निस्तारण नहीं हो जाता है अंतरिम आदेश पारित किया जाए।

सीबीआई विद्वान विशिष्ट अधिवक्ता श्री प्रदीप चौधरी उपस्थित हैं और उनके द्वारा इन प्रकरणों में जवाब प्रस्तुत कर दिए हैं, जो संलग्न पत्रावली रहें।

इस संदर्भ में आदेशिका दिनांक 25.04.2025 के अवलोकन से यह प्रकट हुआ है कि समकक्ष पीठ द्वारा S.B. Criminal Miscellaneous (Petition) No. 1437/2025, 7547/2024, 5577/2023, 8221/2024 के साथ S. B. Crl.W.P. No. 703/2024 एवं S.B. Criminal Revision No.792/2022 को समेकित करने के आदेश दिए गए हैं। इस संदर्भ में क्रिमिनल रिट एवं क्रिमिनल रिविजन का रोस्टर इस न्यायालय के समक्ष नहीं है। अतः प्रोपराइटी

RAJASTHAN HIGH COURT

यही कहती है कि इस प्रकरण में सुनवाई हेतु मामले को प्रशासनिक आदेश पारित करने हेतु माननीय मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष उचित आदेश हेतु रखा जाए।

प्रकरण माननीय मुख्य न्यायाधिपति के समक्ष उचित आदेश हेतु प्रस्तुत हो।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR PRASHAD /5-10